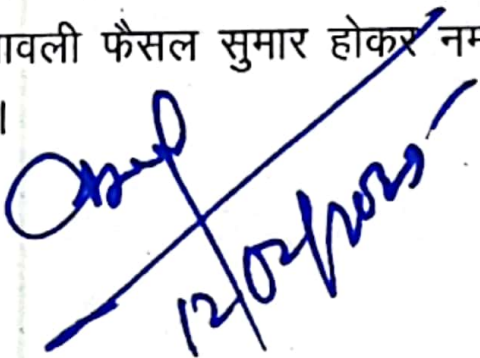


12/2/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपरिथत। विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 8 के अधिवक्ता अनुपरिथत। मूलवाद के आदेशानुसार शेष विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पारित की जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विप्रार्थी अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण विप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर वहस सुनी जावें। दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं की वहस सुनी गई। विप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण विप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। तत्पश्चात प्रार्थीगण अधिवक्ता की वहस सुनी गई और वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी/वादी माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किए जाने का ऐसा कोई औचित्य पूर्ण कारण सामने नहीं आया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्वष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनते हैं।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

A handwritten signature in blue ink is written over a diagonal line. Below the signature, the date '12/02/25' is written in blue ink.